योजना सह रणनीति बैठक

दिनांक 25 - 26 जुलाई, नई दिल्ली

दिनांक 25 - 26 जुलाई 2018 को नासवी के कार्यो के मूल्यांकन एवं योजना सह रणनीति बैठक हेतु कार्यकारिणी समिति की दो दिवसीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई | बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश सिंह ने की |

बैठक में सर्वप्रथम मेघालय शिलांग रोड साइड हाकर एसोसिएशन के अध्यक्ष और नासवी के सदस्य मो शरिफ अहमद के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई | बैठक मे सर्व प्रथम एजेंडे पर चर्चा की गई एवं सर्व सम्मति से एजेंडा पारित की गई | इसमे सदस्यो ने टाउन वेंडिंग कमेटी के कार्यो पर विस्तृत चर्चा की मांग की|

प्लानिंग सह रणनीति बैठक 25 - 26 जुलाई 2018	कार्यक्रम विवरण
प्रथम दिवस - 25 जुलाई, 2018	
11:30 पूर्वाह्न - 12:00 अपराह्न चाय और पंजीकरण	
12:00 अपराह्न - 12:15 अपराह्न	एजेंडा अधिग्रहण
12:15 अपराह्न - 12:30 अपराह्न	गत बैठक का संपुष्टि
12:30 अपराह्न - 01:30 अपराह्न	समन्वयक रिपोर्ट का प्रस्तुति।
01:30 अपराह्न - 02:00 अपराह्न	भोजनवकाश
02:00 अपराह्न - 03:30 अपराह्न	राज्यों से प्रस्तुति
03:30 अपराह्न - 04:00 अपराह्न	स्ट्रीटनेट / कार्यकरणी मे रिक्ति पर चर्चा
04:30 अपराह्न - 05:00 अपराह्न	चाय अवकाश
05:00 अपराह्न - 6:00 बजे	वार्षिक सामान्य सभा बैठक पर चर्चा।
दिन दो - 26 वें जुलाई, 2018	
9:00 पूर्वाह्न - 10:00 पूर्वाह्न	सदस्यता / सदस्यता की स्थिति
10:00 पूर्वाह्न - 11:15 पूर्वाह्न	वितीय रिपोर्ट
11:15 पूर्वाह्न - 11:30 पूर्वाह्न	चाय अवकाश
11:30 पूर्वाह्न - 12:30 अपराह्न	स्ट्रीट फूड फेस्टिवल पर चर्चा
12:30 अपराह्न - 2:00 अपराह्न	भविष्य की कार्य योजना
दोपहर 2:00 बजे	भोजनवकाश एवं कार्यवाही समाप्ती

कार्यकारी अध्यक्ष की अनुमति से समन्वयक ने विगत नवंबर 2017 से जुलाई 2018 के बीच विभिन्न राज्यों में हुई गतिविधियों का ब्यौरा दिया| विभिन्न राज्य में हुई गतिविधियों का ब्यौरा का मुख्य अंश निम्न प्रकार है|

कानून के क्रियान्यावन की स्थिति

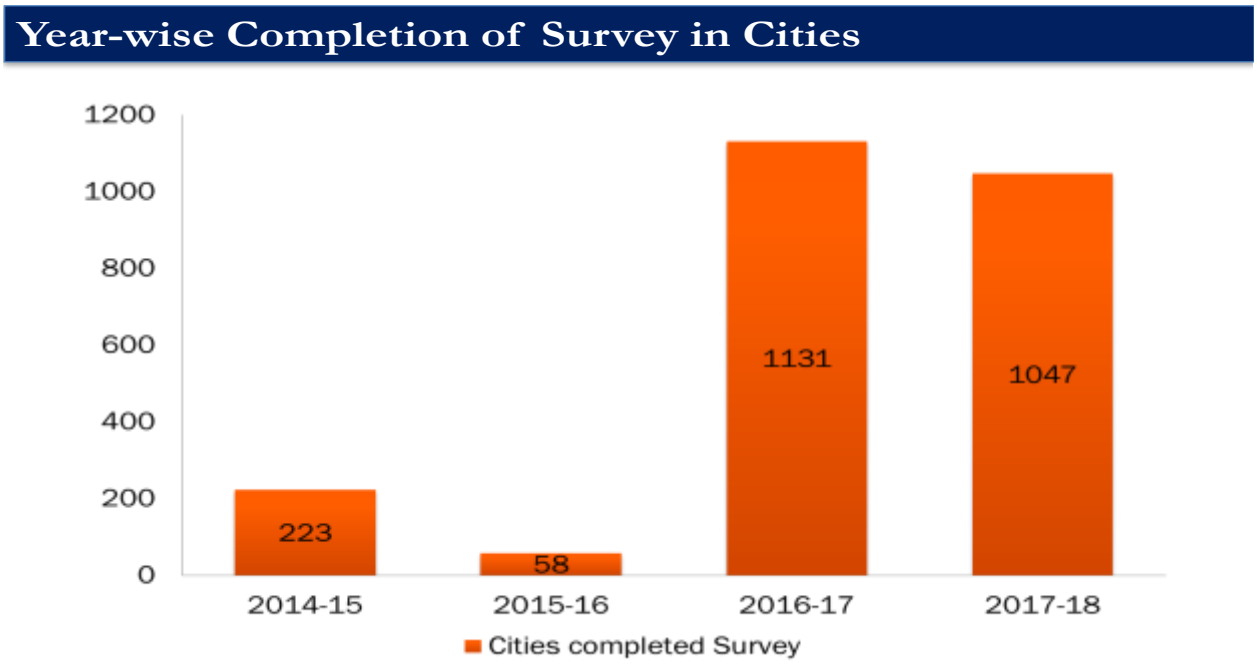

स्ट्रीट विक्रेताओं अधिनियम 2014 का कार्यान्वयन	टाउन वेंडिंग समितियों और योजना की स्थिति
• 30 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अधिसूचित नियम; • 21 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अधिसूचित योजना; • तेलंगाना केवल योजना अधिसूचित, नियम लंबित; • 4 राज्य (अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और पश्चिम बंगाल) - नियम और योजना को सूचित करने के लिए • राज्य अधिनियम: मेघालय	• 21 राज्यों में 2,777 टाउन वेंडिंग समितियां गठित की गई हैं; • 270 टाउन वेंडिंग प्लान 14 राज्यों में पूरा • आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश ने विक्रेता बाजार में बुनियादी ढांचे के विकास के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।

राज्यो मे गतिविधिया

- "चलो संसद - घेरो संसद" विरोध - 21 दिसंबर 2017 देश भर से स्ट्रीट वेंडर के अंधाधुंध उत्पीड़न और बेदखल रोकने और स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट -2014 के उचित कार्यान्वयन को रोकने के लिए अपने अभियान को आगे बढ़ाकर, सड़क विक्रेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध किया।

- 23 मार्च 2018 को प्रवासी भारतीय केंद्र में दीन दयाल अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित किया गया था जिसमें नासवी के राष्ट्रीय समन्वयक ने एक वक्ता के रूप में अपने अनुभव साझा करने को आमंत्रित किया गया था

- पूरे दिल्ली में कुल तीनों नगर निगम मिलाकर के 26 टीवीसी मे कुल 312 सीट के लिए चुनाव की मे 105 सीट पर नासवी समर्थित उम्मीदवार विजयी हुए |

- उत्पीड़न के खिलाफ 14 मई 2018 को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल से वेंडोर्स ने बेदखल अभियान की तत्काल रोकथाम की मांग की। एल-जी ने नासवी से सुधारात्मक सुझाव देने के लिए कहा एवं शहरी विकास विभाग के साथ उठाएंगे।

- झारखंड मे अधिनियम के अनुसार नियमावली बन चुका है एवं जमशेदपुर को स्मार्ट सिटी के रूप मे चयन किया गया है| साकची अधिसूचित छेत्र समिति में टाउन वेंडिग कमेटी का गठन हो गया । नासवी समर्थित झारखंड स्ट्रीट वेंडर्स यूनियन के सदस्य सभी निर्विरोध निर्वाचित चूने गए ।

- नासवी सम्बद्ध लघु व्यापार संगठन ने जनवरी मे नगर आयुक्त को एक ज्ञापन दिया की पहले स्ट्रीट वेंडर एक्ट को नगर मे लागू किया जाय एवं उसी के आलोक मे वेंडोर्स को पुनर्वासित किया जाय | वेंडर संगठन ने टाउन वेंडिंग समिति की बैठक नहीं किए जाने पर भी रोष व्यक्त किए| रुड़की एवं देहरादून मे मे वेंडिंग जोन का निर्माण का कार्य शुरू हुआ एवं हरिद्वार मे महिला स्ट्रीट वेंडोर्स के साथ अंतराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया |

- श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर मे 6 दिसंबर, 2017 को उपमुख्यमंत्री डॉ निर्मल सिंह ने विभागीय प्रशासन , कश्मीर से कहा कि बटामलू बस स्टैंड के सड़क विक्रेताओं के पुनर्वास के लिए संभावनाएं तलाशें।

- 3 मार्च को 2018 को , सरगुर तहसील, मैसूर मे डे-एनयूएलएम द्वारा स्ट्रीट वेंडोर्स को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया । प्रशिक्षण में लगभग 200 विक्रेता मौजूद थे। भास्कर उर्स - नासवी के उपाध्यक्ष (दक्षिण) को प्रशिक्षण में एक पैनलिस्ट के रूप में भी आमंत्रित किया गया था।

- 6 अप्रैल 2018 को सर्किल 29 सिकंदराबाद, जीएचएमसी सर्किल 30 बेगमपेट मे टीवीसी बैठक हुई | इस बैठक में आयुक्त चैंबर जीएचएमसी के अधिकारियों, यातायात पुलिस और स्ट्रीट वेंडर प्रतिनिधियों ने भाग लिया |

- स्ट्रीट वेंडर की ताकत और एकता के संबंध में बिहार , आंध्रा प्रदेश कर्नाटक , असम स्ट्रीट वेंडर्स संघ के नेताओं की बैठक का आयोजन कर जागरूकता कार्यक्रम, क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया गया |

- केरल मे स्ट्रीट वेंडोर्स नियमावली लागू हो चुका है| कोझिकोड व कालीकट,में आईडी कार्ड वितरित किए गए है । कालीकट टीम द्वारा किए गए प्रस्ताव को माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने स्वीकार कर लिया था। प्रस्ताव में स्ट्रीट विक्रेताओं के लिए फाइनेंसियल सहायता और मुख्यधारा के समाज में शामिल होना था।

- गुवाहाटी में चांदमारी और सिक्स:माइल में 2 वेंडिंग क्षेत्र बनाए गए और नलबारी में सात वेंडिंग क्षेत्र बनाए गए। गुहाटी में सुखेश्वर मंदिर से भुर्री तक "फैंसी बाजार" वेंडिंग जोन मेंबनाया गया जो सिर्फ रविवार के लिए है। राष्ट्रीय शहरी जीवनी मिशन (एन.यू.एल.एम) और एफ.एस.एस.ए.आई के सहयोग से 60 रेहड़ी पटरी वालों के लिए गुवाहाटी में एक सुरक्षित खाद्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।
- गत वर्ष महाराष्ट्र मे हुए वेंडोर्स पर प्रहार एवं उसके बाद आज़ाद हाकर यूनियन के प्रतिरोध के फलस्वरूप वेंडोर्स पर अनावश्यक प्रहार मे कमी तो आई है परंतु स्थती संतोषजनक नहीं है| पुणे, मे विक्रेताओं ने 23 जनवरी, 2018 को सड़क विक्रेताओं के बेदखल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वे इस मुद्दे के बारे में आयुक्त से भी मुलाकात की।

- पंजाब मे सर्वेक्षण का कम लगभग पूरा हो गया है एवं लगभग 22000 स्ट्रीट वेंडर का पंजीयन हुआ है | पंजाब के विभिन्न शहरो मे वेंडिंग ज़ोन बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है एवं वेंडिंग कार्ड देने की भी मुकम्मल तैयारी हो चुकी है परंतु कार्य की धीमी प्रगति के कारण अभी बहुत कुछ होना बाकी है| पंजाब मे मुख्यमंत्री द्वारा इस कानून के अनुपालन की दिशा मे समय समय पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये जा रहे है|
- पटना, खगरिया, एवं भागलपुर देहरादून का सीटी वेंडिंग योजना का निर्माण कर आगे की कार्यवाही हेतु नगर निकायो को जमा किया गया| राज्य स्तर कानून के क्रियान्यावन के लिए मानवाधिकार आयोग, जिला जन शिकायत कोषंग, मुख्य मंत्री जन शिकायत कोषंग , टीवीसी अध्यक्ष सह नगर आयुक्त से मदद की रणनीति बनाई गई है |

- जबलपुर, के रेहड़ी पटरी वालों का आई.डी कार्ड का वितरण प्रगति पर है। जबलपुर नगर निगम और टाउन वेंडिंग कमेटी ने जबलपुर में वेंडिंग जोन की पहचान की। जबलपुर नगर निगम द्वारा 19 वेंडिंग जोन पहचाने गए है |

- राजस्थान राज्य सरकार ने स्ट्रीट वेंडिंग नियमावली पारित कर दी है| टीवीएस के चुनाव कुछ नगर निकायों मे हुए है| जोधपुर में ग्यारह वेंडिंग जोन और पांच गैर वेंडिंग जोन की पहचान की गई है। जयपुर में टीवीसी की बैठक में, 85 वेंडिंग ज़ोन की पहचान की है। माउंट आबु मे शहर के सड़क विक्रेताओं के 5 महीने बाद राजस्थान उच्च न्यायालय ने नगरपालिका को अपना खुद का व्यवसाय करने के निर्देश दिए हैं।
- उत्तर प्रदेश के 72 शहरों में अभी तक टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) का गठन हो गया है। इलाहाबाद के सिविल लिने मे स्मार्ट सिटि अंतर्गत वेंडिंग ज़ोन बनाने के लिए प्रशाशन ने अपनी मंजूरी दे दी है| लखनऊ, मेरठ, गाज़ियाबाद, वाराणसी , आगरा,इलाहाबाद, मुरादाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर समेत कुल 14 नगर निकायो मे 1.96 लाख स्ट्रीट वेंडोर्स को परिचय पत्र दिया जाने हेतु चिन्हित किया गया है|

- वर्ष 2018 मे भी स्ट्रीट वेंडोर्स फ़ैडरेशन ने स्ट्रीट वेंडोर्स दिवस को अपने ढंग से अपने जरूरत के अनुसार आयोजित किया |

- नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का 9वां संस्करण नासवी और खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा 12 वीं से 14 जनवरी, 2018 तक आयोजित किया गया था।

- नासवी ने नेस्ले इंडिया के एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के साथ मिलकर परियोजना सेव सुरक्षित खाद्य कर रहा है भारत भर में 9500 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं लाभान्वित हो चुका है।

- नासवी ने 23 मार्च को , स्ट्रीट वेंडर ने नासवी के साथ जुड़ने एवं स्ट्रीट फूड वेंडर स्वास्थ्य और स्वच्छ प्रशिक्षण प्राप्त के बाद के अपने अनुभव को हयात होटल में साझा किया।

- छत्तीसगढ़ में संगठन को पहचान किया है, रायपुर और भिलाई में संगठन का कार्य शुरू हुआ है और वहां से सदस्यता के लिए भी आवेदन आए हैं |

समन्वयक के प्रतिवेदन पर चर्चा के दौरान विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव व बिन्दुओ को समिति के समक्ष रखे |

उत्तरांचल - श्री संजय चोपड़ा ने बताया कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के द्वारा एक संबंध स्थापित किया जाए कृषि मंत्रालय के द्वारा राज्य में "अपना बाजार योजना" के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में वेंडर को सहयोग किया जा सकता है| अपना बाजार योजना के तहत किसानों को बाजार मुहैया कराया जाता है इसमे वेंडर को बाजार मुहैया कराया जा सकता है| हरिद्वार में टाउन वेंडिंग कमेटी की पहली बैठक 26 जुलाई को निर्धारित है| नेशनल हाईवे को के किनारे भी वेंडर को समायोजित करने हेतु हम लोगों को एक रणनीति बनानी चाहिए | नैनीताल में माल रोड पर वेंडर को हटाया जा रहा है हमने नैना देवी मंदिर के पास उनको बसाने हेतु चर्चा आयुक्त से की है | यह भी देखा जाता है कि संसदीय चुनाव के समय नजदीक आने पर सरकार ने कुछ-न-कुछ वेंडर को दिया है |2004 हो या 2009 या 2014 हो, नीति एवं कानून हमेशा आम चुनाव से पूर्व ही मिला है अतः हमें इस सरकार से भी 2019 में आम चुनाव को देखते हुए वेंडोर्स के हितार्थ कदम उठाने चाहिए |

मध्यप्रदेश - गोपाल सिंह लोधी जबलपुर में 12 वेंडिंग ज़ोन बनाए गए हैं | 35000 वेंडोर्स का सर्वे हो चुका है हमने नासवी के तरफ से नगर आयुक्त को एक पत्र भेजवाया है जिसमें 2014 के कानून को अक्षरसः पारित कराने हेतु मांग किया गया है | नासवी को सुझाव है कि विभिन्न राज्यों के नियमावली को मांगा करके उसका अध्ययन करें कि वह सही है या नहीं | मध्य प्रदेश में कुल 51 जिले हैं, सभी जिलों में समान रुप से कार्य नहीं हो रहा है | हमने जबलपुर में 4000 लोगों को आयुक्त महोदय से पहचान पत्र दिलवाया है और उनसे ₹60 का सदस्यता शुल्क भी दिए जा रहे हैं जिसका टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में निर्णय हुआ था|

उत्तरप्रदेश- वाराणसी, श्री अभिषेक निगम ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर नगर आयुक्त एवं जोनल ऑफिसर के साथ बैठक हुई है जिसमें 29 वेंडिंग जोन पर सहमति बनी है | सभी स्थानों पर एनओसी के लिए आवेदन दे दिए गए हैं और इस संदर्भ में अगले 2 अगस्त को एक बैठक आहूत की गई है | नगर निगम के पास ही एक फूड वेंडिंग ज़ोन बनाने की भी चर्चा की गई है | इसके साथ ही गाजीपुर और आसपास के शहरों में भी टाउन वेंडिंग कमेटी बनाने मे मदद की गई है | **लखनऊ से श्री गोकुल प्रसाद** ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एवं स्टेट एवं टाउन वेंडिंग कमेटी के बीच में काफी शून्यता है | टाउन वेंडिंग कमेटी के बैठक मे बाकी पदाधिकारी नहीं आते हैं | कानून का औचित्य समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कानून का अनुपालन राज्यों में ठीक ढंग से नहीं हो रहा है एवं राज्य शहरी आजीविका मिशन के जो भी पदाधिकारी हैं उनकी बहुत समझ कानून के विषय में नहीं है | अतः नासवी को कानून का एक संक्षिप्त रूप में बनाकर NULM को भेजना एवं टाउन वेंडिंग कमेटी को भेजना चाहिए|

पंजाब से श्री टाइगर सिंह ने बताया कि एक तरफ कानून का पूरा अनुपालन नहीं किया जा रहा है दूसरी तरफ वेंडर से जुर्माना भी लिया जाता है | जो वेंडर बैठ कर के भेजते हैं उनसे ₹3200 एवं जो बिना छतरी के बेचते है उनसे ₹1600 जुर्माना किया जा रहा है अतः इसमे हस्तक्षेप की जरूरत है |

कर्नाटक से मो. अनवर ने बताया कि नासवी का राज्य में कोई ऑफिस नहीं होने की वजह से समन्वय स्थापित करने में काफी कठिनाई होती है | अतः नासवी का एक स्टेट ऑफिस होना चाहिए , जो भी सदस्यता प्रपत्र आते हैं वह राज्य से होकर केंद्र के पास आना चाहिए | **श्री संजय चोपड़ा एवं श्री गोकुल प्रसाद** ने उनके इस प्रस्ताव का समर्थन किया | श्री प्रसाद ने कहा कि इससे पूर्व भी राज्यों में स्टेट कमेटी बनी थी लेकिन स्टेट कमेटी के पास किसी भी तरीके का कोई फंड नहीं होने की वजह से वह कमेटी काम नहीं करें नहीं कर पाए अतः यह सोचना होगा कि स्टेट कमेटी कैसे कार्य करेगी एवं उसके पास किस प्रकार से फ़ंड आएगा |

दिल्ली श्री सागर यादव - हमें पुरजोर व्यवस्था बनाने की जरूरत है लेकिन यह देखना होगा कि इस व्यवस्था को चलाएगा कौन ? इसका संचालन किस स्तर पर होगा ? श्री संजय चोपड़ा ने कहा की पूरे स्टेट में हमारी कमेटी है, मई किसी भी तरीके का फंड नहीं लेता एवम ना ही मार्केट कमेटी से किसी भी तरीके का फंड लेता हूं जहां पर पैसे का सवाल होगा वहाँ संगठन ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा | अतः आपसे अनुरोध है कि राज्य के संगठन कैसे चलेंगे इस पर एक दिशा निर्देश बनाकर सभी राज्य कमेटी को भेजा जाय|

असम -श्री देबोजित - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के पदाधिकारियों को स्टेट का सपोर्ट नहीं मिल पाने की वजह से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक के तहत जो राशि है उसका उचित उपयोग नहीं हो पा रहा है एवं काम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है | किस विधि से इन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित किया जाए यह मेरे लिए एक बड़ा विचारणीय सवाल है |

तमिलनाडु - वी मंगेश्वर - तमिलनाडु में कुल 125 नगर निकाय हैं, सभी नगर निकायों में टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन हो गया है | पहचान पत्र देने की प्रक्रिया भी चल रही है परंतु अभी तक एक भी वेंडिंग ज़ोन नहीं बनाया गया है | पहचान पत्र देने के बाद भी वेंडोर्स को हटाया जा रहा है | नेशनल हाईवे के पास से भी हटाया जा रहा है | नगर निगम और पुलिस के बीच में कोई रचनात्मक संबंध में नहीं है | राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के पदाधिकारियों एवं नगर निकायों में काफी रिक्तता है | वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी करने का प्रारूप कैसा होना चाहिए यह भी उनको नहीं मालूम है | वह टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में भी नहीं आते | हमने आरटीआई के माध्यम से इंफॉर्मेशन मांगा है जिसको देने में लेट किया जा रहा है | अतिक्रमण हटाने के मामले में हाईकोर्ट में जो मामले चल रहे हैं उस मामले में स्ट्रीट वेंडर्स का पक्ष नहीं दिया जाता , ना ही अधिकारी कोर्ट मे स्ट्रीट वेंडर अक्त 2014 की जानकारी देते हैं | हमें इस तरीके के मामले में दखल देना चाहिए |

राजस्थान - श्री ओमप्रकाश देवड़ा -टाउन वेंडिंग कमेटी के क्या कार्यकलाप हैं - यह टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्यों को जानकारी नहीं है, अतः नासवी को टाउन वेंडिंग कमेटी के कार्यों को सुचारु संचालन के लिए एक पंपलेट बनवाकर नगर निकायों को भेजना चाहिए | साथ ही उन्होंने यह सुझाव दिए कि नासवी के जो सक्रिय प्रतिनिधि है वे दूसरा शहरों में या दूसरे राज्यों में जाकर के वेंडोर्स के साथ बैठक करें ताकि स्टेट बादल कर काम करने से दूसरे राज्य समितियों को भी एक नई ऊर्जा का संचालन होगा | नासवी को राज्य में वैसे अधिवक्ताओं को जो स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट करते हैं उनको प्रोत्साहन पत्र या प्रशस्ति पत्र जरूर निर्गत करना चाहिए |

चर्चा के उपरांत रणनीति

- प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के कार्यों के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स कानून के तहत किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा बैठक होती है , हमें यह रणनीति बनाने चाहिए कि हम इस बैठक के भागीदार कैसे हो सकते हैं इस पर हमें राज्यों में चर्चा करनी चाहिए

- दिल्ली में अभी टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव हुआ है , उन्होंने बिगो से अनुरोध किया है कि वह नई दिल्ली में कमेटी के सदस्यों का एक दिन का प्रशिक्षण करवाएंगे इसके लिए उन्होंने भी weigo से आर्थिक सहायता मांगी है |

- स्टेट ऑफिस के सवाल पर चर्चा हुई की अभी फंड की बहुत समस्या है कोई भी बाहरी दाता संगठन सहयोग करने के लिए तैयार नहीं होते हैं , उनके लिए अपने एक शहर विशेषता एक मायने रखती है | सरकार के साथ काम करना हमेशा एक जोखिम भरा काम होता है लेकिन रिसोर्स मोबिलाइजेशन का कार्य भी अत्यंत मुश्किल होता है | स्टेट का कार्यालय कैपिटल सिटी में हो तो ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि सरकार उसी संगठन को ज्यादा तवज्जो देती है जिसका संगठन कार्यालय कैपिटल सिटी में हो | जो भी संगठन सक्षम है वह स्टेट में अपना कार्यालय खोल सकते हैं लेकिन संगठन के स्वरूप को देखना पड़ेगा कि संगठन किस तरीके से वह कार्य कर सकता है और राज्य की प्रशासनिक इकाइयों के साथ संबंध स्थापित कर सकता है |

स्ट्रीट नेट की सदस्यता एवं नासवी के कार्यकारिणी समिति में रिक्त पदों पर परिचर्चा

समन्वयक श्री अरविंद सिंह ने स्त्री एवं नासवी के संबंधों पर पर चर्चा करते हुए कहा कि नासवी की स्ट्रीट नेट में सबसे बड़ी भागीदारी है लेकिन इस भागीदारी के बावजूद भी स्ट्रीट नेट इंटरनेशनल - नासवी को उचित स्थान मिलना देती | हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एशिया का फोकल पॉइंट नेपाल को बनाकर नासवी जैसे संगठन की अनदेखी की गई है | अतः यह प्रस्ताव लाया जाता है कि स्ट्रीट नेट इंटरनेशनल की सदस्यता समाप्त की जाए और अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक नए ग्लोबलाइजेशन का गठन किया जाए जिसमें अर्जेंटीना स्पेन एवं अन्य एशियाई देशों का भी समर्थन प्राप्त है|

कार्यकारिणी परिचर्चा के उपरांत समिति ने इस बात में भरोसा जताया इस स्ट्रीट नेट इंटरनेशनल के साथ नासवी के संबंध जग जाहिर है एवं गत वर्ष स्ट्रीट नेट इंटरनेशनल कांफ्रेंस दिल्ली मे नासवी ने आयोजित किए थे उसमें भी इस बात को प्रत्यक्ष रुप से नासवी की कार्यकारिणी समिति ने महसूस किया था अतः समन्वय के प्रस्ताव पर कार्यकारिणी समिति ने मुहर लगाते हुए उन्हें इस बात के लिए अधिकृत किया कि वह एशियाई देशों एवं दूसरे अन्य देशों के साथ मिलकर एक ग्लोबल ऑर्गनाइजेशन को खड़ा किया जाए|

समन्वयक ने यह भी प्रस्ताव लाया गत कार्यकारिणी समिति में जिस तरीके से अध्यक्ष ने बैठक की कार्यवाहियों को बहिस्कार किया एवं सदस्यो को अपमानित किया उसके बाद उन्हें अध्यक्ष पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है अतः समिति के समक्ष या प्रस्ताव लाया जाता है कि श्री चंद्रप्रकाश सिंह जो वर्तमान मे नासवी के उपाध्यक्ष है उनको अध्यक्ष के रूप मे चुन लिया जाय|

उपरोक्त प्रस्ताव पर कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने विस्तृत चर्चा की जिसमें श्री चन्द्र प्रकाश सिंह ने स्ट्रीट नेट मे अपने चुनाव लड़ने के अनुभव को साझा किया इसी प्रकार गोकुल गोकुल प्रसाद एवं सागर यादव ने भी

इंटरनेशनल कार्यक्रम के दौरान अपने अनुभव को साझा किया | गोकुल प्रसाद एवं श्री कृष्ण गोकुल प्रसाद एवं गोपाल सिंह लोधी ने मध्य प्रदेश में सेवा इंदौर के साथ अपने अनुभव को साझा किया कि किस तरीके से इस बड़े ऑर्गनाइजेशन ने छोटे आर्गेनाईजेशन को प्रताड़ित करने का काम किया है

दोनों ही प्रस्ताव पर कार्यकारिणी समिति की सहमति बनी एवं दोनों ही प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए | सदस्यो ने नव निर्वाचित अध्यक्ष को बधाई एवं शुभकामनाए दी|

वार्षिक सामान्य सभा बैठक पर चर्चा

वार्षिक आम सभा नई दिल्ली मे करने पर सहमति बनी | परिचर्चा करते हुए यह निर्णय लिया गया कि 12 से 19 सितंबर 2018 के बीच वार्षिक आम सभा के लिए तारीख निर्धारित कर लिया जाए | नगर विकास के केंद्रीय मंत्री को इस कार्यक्रम मे आमंत्रित किया जाय | विभिन्न राज्यो से भी मंत्री / नगर निकाय अधिकारी / एवं वैसे लोगो को आमंत्रित किया जाय जिनका कुछ योगदान वेंडोर्स के लिए है|

वार्षिक आम सभा के दौरान स्ट्रीट फूड वेंडर पर एक अलग से एक सत्र रखने की मांग की गई |

यह भी मांग की गई कि विभिन्न राज्यों में जो स्ट्रीट वेंडर्स लीडर्स ने अच्छे काम किए हैं उन को पुरस्कृत किया जाए |इस विषय पर विस्तृत पर चर्चा के बाद यह निर्णय हुआ की पांच वेंडोर्स को चयन किया जाएगा एवं इसके लिए एक त्रि स्तरीय कमेटी गठित होगी, यह कमेटी विभिन्न राज्यों से नॉमिनेशन आमंत्रित करेगी एवं पांच सदस्यों को चयन करेगी इन सदस्यों को वार्षिक आम सभा के दौरान पुरस्कृत किया जाएगा |

सदस्यता / सदस्यता की स्थिति

वर्तमान मे विभिन्न राज्यों में 641 संगठनों के 869299 स्ट्रीट वेंडर सदस्यों NASVI से जुड़े हुए है । छत्तीसगढ़ उड़ीसा महाराष्ट्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना राजस्थान से कुल 21 सदस्य नए सदस्यता हेतु आवेदन पत्र कार्यकारिणी समिति के समक्ष समक्ष रखे गए, जिस पर गहन चर्चा के बाद कुल 21 संगठनों में से 14 संगठनों को नासवी की संबद्धता लिए प्रस्ताव पारित किया गया एवं 7 सदस्यों को पर पुनर्विचार हेतु उस राज्य के कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को प्रेषित किया गया |

वित्तीय प्रतिवेदन

नासवी के कोषाध्यक्ष श्री कमलेश उपाध्याय ने नासवी का लेखा जोखा प्रस्तुत किया | वित्तीय प्रतिवेदन की प्रति सभी सदस्यों के बीच वितरित की गई | यह लेखा-जोखा दिनांक 1-11-2017 376 2018 के बीच के कुल व खर्चे के बाबत बताया गया था | जिसे परिचर्चा उपरांत सर्वसम्मति से पारित किया गया |

स्ट्रीट फूड फेस्टिवल पर चर्चा

स्ट्रीट फूड कोऑर्डिनेटर सुश्री संगीता सिंह ने कहा की स्ट्रीट फूड फेस्टिवल जनवरी 2018 में नासवी स्ट्रीट फूड प्राइवेट लिमिटेड एवं FSSAI द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था जिसका कुछ मिलाजुला अनुभव रहा | अपने अनुभव को बताते हुए उन्होने कहा की गत वर्ष का फूड फेस्टिवल हमारे नजर में थोड़ा कमजोर रहा क्योंकि हमारी और organizing बहुत सही नहीं थी, जनवरी का समय भी अनुकूल नहीं था | हमारा खर्च बहुत

ज्यादा रहा जिसके अनुपात में बिक्री कम हुई , लेकिन इस फूड फेस्टिवल की सबसे अच्छी बात यह रही कि एफ़एसएसएआई हमारा पार्टनर बना |

उन्होने वर्ष 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय फूड फेस्टिवल को आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया है | उन्होंने बताया कि इस वर्ष कुल 60 स्टॉल लगाने का प्रस्ताव है जिसमें भारत सहित दूसरे देशों से भी स्टॉल होंगे | अंतर्राष्ट्रीय फूड फेस्टिवल का प्रस्तावित तारीख 14 15 16 दिसंबर 2018 में नई दिल्ली में ही है , यद्यपि जगह इस बार बदलने की बात की जा रही है और हम जगह की तलाश में है | हमने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को भी पत्र लिखा है कि वह हमें इस इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में सहयोग करें और FSSAI ने भी हमे इस कार्यक्रम के लिए सहयोग करने के लिए भी अपनी सहमति दी है|

चर्चा के दौरान सदस्यों ने अपने भी कुछ सुझाव दिए

- प्रवेश शुल्क 100 रु रुपया रखा गया था जो कि ज्यादा था यह ₹50 से ₹60 के बीच में होना चाहिए |
- जो भी समान वेंडर के उपयोग में आने वाला है उसका कीमत की सूची पहले से ही वेंडर को दे दिया जाना चाहिए |
- दिल्ली से ज्यादा वेंडर होने से दूसरे राज्यों से आने वाले वेंडर को परेशानी होती है
- फूड कमेटी की बैठक नियमित रूप से होनी चाहिए | इस संदर्भ में संगीता जी ने बताया कि पूर्व में गठित फूड कमेटी से 2 से 3 सदस्य स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में नहीं आते अतः समिति की बैठक नहीं हो पाती | समिति ने उन्हें सुझाव दिया कि वह पुनः 5 सदस्य कमेटी का गठन करें |
- फूड वेंडर को यह इस बात की इजाजत दी जाए कि वह अपने शहर से अपना इंग्रेडिएंट्स लेकर के आए|
- वेंडर स्वयं अपना सामान खरीदे यदि संभव हुआ तो नासवी द्वारा उनको कुछ अग्रिम भुगतान किया जाय|

कार्य योजना एवं भविष्य रणनीति

- सरकार पर स्ट्रीट वेंडर कानून 2014 को लागू करवाने हेतु हम और कैसे दबाव बना सकते हैं इस पर हमें राज्य समिति की बैठक मे विचार करने की आवश्यकता है

- अपना बाजार के साथ संपर्क में रहने के लिए कृषि विभाग की योजना को समझा जाए एवं कृषि विभाग भारत सरकार के साथ संपर्क स्थापित किया जाए

- केंद्र में अतिक्रमण संबंधी जो कानून बनाया जा रहा है उस कानून में वेंडोर्स के हितार्थ क्या किया जा सकता है इस संदर्भ में पहल किया जाएगा

- वेंडोर्स को हक़ मे संघर्ष करते हुए उनके लीडर्स या उनके प्रतिनिधि कई बार जिला प्रशासन एवं अन्य तत्वों द्वारा निशाने पर ले लिया जाता है , ऐसी स्थिति में नासवी को एक स्पष्ट रुप बनाना होगा कि इस तरह के लीडर्स व प्रतिनिधि को किस तरीके से मदद किया जा सकता है|

- संसद में आश्वासन समिति के माध्यम से यह स्ट्रीट वेंडोर्स कानून के अनुपालन का मुद्दा उठाया जाए|

- दुकान आवंटन के मामले में नासवी को एक स्पष्ट दिशा निर्देश बनाकर राज्य सरकार एवं टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्यों को भेजना जाय|

- राज्य एवं शहर के स्तर पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए टाउन वेंडिंग कमेटी एवं सिटी लेवल फ़ैडरेशन को कार्यों के आधार पर एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाकर के टाउन वेंडिंग कमेटी को भेजा जाय|
- ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी के गठन हेतु जोर देना चाहिए एवं नासवी द्वारा प्रत्येक राज्य सरकारों को पत्र लिखना चाहिए |
- नेशनल एडवाइजरी काउंसिल को भी ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी के गठन हेतु पत्र लिखना जाय|
- 29 -30 जुलाई को लखनऊ में टाउन वेंडिंग कमेटी का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा |
- 13 सितम्बर को वाराणसी मे स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के इंप्लीमेंटेशन पर एक वर्कशॉप आयोजित किया जाएगा|
- राज्य में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो वकील काम कर रहे हैं , इन वकीलों को पहचान करके उन्हें सम्मानित किया जाएगा |
- देश भर से 5 स्ट्रीट वेंडर्स के चयन के लिए त्रि स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा |
- टाउन वेंडिंग कमेटी के कार्य करने कार्य प्रणाली के लिए एक मार्गदर्शिका बनाया जाएगा|
- टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्यों के समक्ष आने वाले संभावित प्रश्नों को दृष्टिगत करते हुए उसके संभावित उत्तर की तलाश करके एक मार्गदर्शिका बनाई जाएगी |
- अलग-अलग भाषा में विभिन्न तरह के पंफ्लेट बनाकर के नासवी के वेबसाइट पर डाला जाय|
- WEIGO की वार्षिक आम सभा साउथ अफ्रीका में प्रस्तावित है इसमें नासवी से 2 प्रतिनिधियों को भेजे जाने की योजना है जिस पर वार्षिक आम सभा के दौरान चर्चा किया जाएगा
- वार्षिक आम सभा की बैठक के 1 दिन पूर्व नासिक के कार्यकारिणी समिति की बैठक होनी चाहिए|

अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई|